

भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड 14 में प्रकाशनार्थ
संख्या फा. 1/9/79-स्था 0 भाग 1

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6^{15 Dec} 1983

अधिसूचना

राष्ट्रपति, सतिधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड 5 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में नियुक्त महानेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् मूल नियम का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1- §18 इन नियमों का संक्षिप्त नाम मूलदूसरा संशोधन नियम, 1983
§28 ये 5 अक्टूबर, 1981 से प्रवृत्त हुए समझे जाएँगे।

2- मूल नियम के नियम 22 ग के पहले परन्तुक में, "सरकारी सेवक किसी वर्ग 1 के ही उच्चतर पद में" शब्दों और अंक के स्थान पर "सरकारी सेवक किसी ऐसे उच्चतर पद में जो एक वर्ग 1 का पद है और जिसके वेतनमान का न्यूनतम 1500 रु० से अधिक है," शब्द और अंक रखे जाएँगे।

एस० हरिहरन
§एस० हरिहरन§

अवर सचिव, भारत सरकार

स्पष्टीकारक ज्ञापन - इस नियम का भूतलक्षी रूप से संशोधन किया जा रहा है चूंकि उपरोक्त आशय के कार्यवाहक अनुदेश फा० ज्ञा० फा० 1/9/79-स्थापना-भाग 1 में तारीख 5.10.1981 को जारी किए गए थे। भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी सरकारी सेवक के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है चूंकि यह संशोधन फायदाप्रद प्रकृति का है।

एस० हरिहरन
§एस० हरिहरन§

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः- मूल नियम के नियम 22-ग का पहले निम्नलिखित अधिसूचना में
भाग संशोधन दिया गया है:-

- 1- वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं० फा० ११११/स्था०-१११/६१,
तारीख - १ फरवरी, १९६३
- 2- वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं० फा० ११११/स्था०-१११/६४-
भाग-११, तारीख १८ जुलाई, १९६७
- 3- वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं० फा० ११११/स्था०-१११/७४०,
तारीख ३० अक्टूबर, १९७४

सं० फा० नि० सं० १२०८, भारत के राजपत्र के
तारीख १६ नवम्बर, १९१४ के अंक में प्रकाशित की गई
२५ कार्तिक, १८९६

सेवा में,

मुख्य,

भारत सरकार मुद्रणालय,

राजगपुरी, नई दिल्ली ।